

सीमापार आतंकवाद : भारतीय सुरक्षा चुनौतियाँ एवं विकल्प

प्रो० सतीश चन्द्र पाण्डेय¹

अनुराग दूबे²

सारांश

वर्तमान में आतंकवाद की समस्या एक विश्वव्यापी गंभीर समस्या बन गई है जो विश्व भर के विकसित एवं विकासशील देशों में कानून, प्रशासन व समाज के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपनी स्वार्थसिद्धि और राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर प्रकार की शक्ति तथा अस्त्रों-शस्त्रों के प्रयोग करने में विश्वास रखती है। अस्त्रों-शस्त्रों का ऐसा घृणित प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग, समुदाय, संप्रदाय अथवा राष्ट्र विशेष को गैर-कानूनी ढंग से डराने धमकाने, जान से मार देने, हिंसा के माध्यम से सरकार को गिराने तथा शासन तंत्रों पर प्रभुत्व जमाने के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार आतंकवाद उस प्रवृत्ति को कहा जा सकता है जिसके माध्यम से कतिपय अवांछित तत्व अपनी सभी प्रकार की मांगों मनवाने के लिए अनेकानेक प्रकार के घोर हिंसात्मक उपायों एवं जघन्य अमानवीय साधनों और अस्त्रों-शस्त्रों का प्रयोग करते हैं। आज विश्व के लगभग सभी देश आतंकवाद की चपेट में आ चुके हैं। राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए आर्थिक हितों की प्राप्ति हेतु, सांस्कृतिक सर्वोच्चता के लिए आतंकवादी सार्वजनिक हिंसा और सामूहिक हत्याओं का कुत्सित रास्ता अपना रहे हैं।

विश्व के लगभग सभी देशों में कुछ न कुछ संकट अवश्य विद्यमान है जिनसे उनके व्यवहारों में परिवर्तन स्वाभाविक है ये संकट दोनों देशों के बीच किसी भी मुद्दों पर हो सकती है जैसे सीमा विवाद, आतंकवाद, व्यापार, आदि के द्वारा संकट का सामना करना पड़ता है। आज पूरा विश्व आतंकवाद की समस्या से परेशान है जिसमें भारत तथा पाकिस्तान की समस्या भी इन्हीं में

¹आचार्य, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर

²शोध छात्र, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय, गोरखपुर, ई.-मेल: anurag.dubeey@gmail.com

से एक है जिनके बीच सीमा विवाद तथा आतंकवाद जैसी समस्याएं हैं।

भारत-पाकिस्तान दोनों सामरिक दृष्टिकोण से परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं परन्तु इनके बीच सीमा विवाद तथा आतंकवाद का मुख्य मुद्दा प्रमुख रहा है। भारत-पाकिस्तान का संबंध शुरू से ही अच्छा नहीं रहा है क्योंकि इन्होंने कई लड़ाईयां लड़ी (1947-48, 1965, 1971 और 1999) हैं। जिसमें सभी युद्ध में भारत के हाथों पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है।

आतंकवाद भारत तथा पाकिस्तान के बीच मुख्य मुद्दा है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान छद्म युद्ध का सहारा ले रहा है जिसमें सीमापार आतंकवाद और राज्य-प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है जिससे भारत को काफी नुकसान हो रहा है। आतंकवाद को हम एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के विरुद्ध एक रणनीति के तहत प्रयोग कह सकते हैं। आतंकवाद का अर्थ है भय पैदा करना अर्थात् जनता में भय पैदा करना तथा जनता और सरकार को जानमाल का नुकसान पहुँचाना ही आतंकवाद है। आतंकवाद का कुछ उद्देश्य होता है जिसको पूरा करने के लिए संगठित संगठन होता है जिस पर किसी राज्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संरक्षण प्राप्त होता है।

मुख्य शब्द: आतंकवाद, आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002, भारतीय सीमा, मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC), फाइनैशियल एक्शन टास्क फोर्स, व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS), भारत-पाकिस्तान सीमा, भारत-बांग्लादेश सीमा, भारत-चीन सीमा, भारत-नेपाल सीमा, भारत-भूटान सीमा, भारत-म्यांमार सीमा इत्यादि।

प्रस्तावना

आतंकवाद समकालीन युग की सर्वाधिक ज्वलंत समस्या है। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इस समस्या से ग्रसित न हो। पिछले कुछ दशकों में इसका दायरा निरन्तर बढ़ता जा रहा है और आज यह सुरसा के मुंह की तरह विभिन्न रूपों में फैल रहा है। आतंकवाद को भिन्न-भिन्न रूप से परिभाषित किया जाता है यहां तक कि आज भी सभी देश इसकी किसी एक परिभाषा पर सहमत नहीं हैं। सामान्य रूप में जब भी किसी व्यक्ति अथवा संगठन के द्वारा अपनी (उचित अथवा अनुचित) बात को मनवाने के लिए अवांछित साधनों बल प्रयोग, शास्त्रास्त्रों, हिंसा आदि का प्रयोग किया जाता है आतंकवाद कहलाता है समस्यात्मक प्रश्न यह उठता है कि जिन हिंसात्मक गतिविधियों को कुछ देशों के द्वारा आतंकवाद कहा जाता है उन्हें कट्टरपंथी मुसलमान जेहाद, फिलिस्तीन व कश्मीर जैसे भू-भागों को स्वतंत्र देश बनाने की तमन्ना रखने वाले स्वतंत्रता की लड़ाई, अमेरिकी अहम के विरोधी उत्पीड़न व

शोषण के विरुद्ध संघर्ष तथा तटस्थ सोच वाले क्रिया की प्रतिक्रिया कहते हैं।

दुनिया में कहीं भी यदि नौजवान दिग्भ्रमित होकर आतंकवाद का रास्ता अपना रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण गरीबी और बेरोजगारी है, क्योंकि दुनिया में फैली आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जाता है इसलिए अराजकवादी ताकतें व्यक्ति की असमानता एवं असुरक्षा की भावना को अपने हितों की दृष्टि से प्रयोग करती है और व्यक्ति को आतंकवाद की गर्त में ले लेती हैं।

आतंकवाद की समस्या का समाधान किसी भी एक देश के द्वारा नहीं किया जा सकता है बल्कि सभी देशों को एक साथ मिलकर रणनीति बनानी होगी तभी आतंकवाद रूपी दानव से निपटा जा सकता है। आतंकवाद रोकने हेतु रणनीति बनाने के साथ उनका क्रियान्वयन भी सक्रिय रूप से किया जाना चाहिए तथा अपेक्षित परिणाम हेतु जनता को भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ना चाहिए तभी इस समस्या पर नियन्त्रण पाया जा सकता है।

निस्सन्देह, युद्ध मानव जाति के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक तो रहा ही है साथ ही प्राचीन काल से वर्तमान तक युद्ध मानव जाति की सम्पूर्ण गतिविधियों पर किसी न किसी रूप में प्रभावी भी रहा है। मानव अपनी उत्पत्ति से ही संघर्ष करता आया है और आज भी कर रहा है। सन् 1861 में एक प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार ने कहा था कि युद्ध ने मानव समाज के विविध पहलुओं में इस भाँति झनझनाहट (Clinks) पैदा कर दी है कि अब समाज का कोई भी पहलू अपने को इससे अप्रभावित नहीं रख सकता। Walter Millis ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि समाज का कोई भी पहलू युद्ध से अछूता नहीं रह सकता।

वाल्टेयर की मान्यता है कि इतिहास मुख्य रूप से हिंसा, विनाश, मानव दुखों तथा मृत्यु की घटनाओं से भरा पड़ा है तथा विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सशस्त्र संघर्ष तो अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास की एक साधारण घटना है। पुरातन काल से ही एक जाति दूसरी जाति से, एक समाज दूसरे समाज से तथा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से संघर्ष करता आया है। इतिहास इसका साक्षी है कि विश्व में हो रहे आर्थिक, राजनैतिक, कूटनीतिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी में परिवर्तनों के कारण युद्ध की प्रकृति व क्षेत्र

में परिवर्तन तो होते रहे हैं परन्तु युद्ध अन्तिम रूप से कभी समाप्त नहीं हुआ।

विश्व इतिहास का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि विश्व में बहुत अल्प समय ऐसा रहा है जिसमें शान्ति कायम रही। नार्वे के एक प्रसिद्ध साख्यिकी-वेत्ता ने सन् 1960 में कम्प्यूटर की सहायता से मानव इतिहास के 5560 वर्षों का अध्ययन करके यह बताया कि इस कालावधि में 2.6135 युद्ध प्रतिवर्ष की दर से 14,351 युद्ध हुए हैं तथा मनुष्य की 185 पीढ़ियों में से केवल 10 ने ही शान्ति की अनुभूति की है। इन्हीं कारणों से क्विसी राइट ने “युद्ध को मानव समाज की एक साधारण दशा” कहकर सम्बोधित किया है। पत्थर युग से अब मानव के अन्तरिक्ष युग में प्रवेश से युद्धों का क्षेत्र तो व्यापक हुआ ही है साथ ही युद्धों को रोकने के प्रयास निष्फल से दृष्टिगत हो रहे हैं। वास्तव में, सीमित युद्धों की निरन्तरता ने युद्ध की समस्या को राजनीति की न सुलझने वाली सबसे बड़ी पहेली (The greatest unresolved riddle of politics) बना दिया है।

भारत के पास सबसे लंबी और सबसे विविध अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों ने भारत को एक कृत्रिम अप्राकृतिक सीमा के साथ छोड़ दिया है। सीमा प्रबंधन सीमाओं के प्रति एक अभिन्न दृष्टिकोण है जिसमें सुरक्षा वृद्धि के साथ-साथ बुनियादी ढांचा और मानव विकास किया जाता है। चीन और पाकिस्तान के साथ लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय और सीमा विवादों से निपटने की चुनौती, दुनिया के कुछ सबसे कठिन इलाकों के साथ झरझरा सीमाओं के साथ, प्रभावी और कुशल सीमा प्रबंधन को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया है।

आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002

यह आतंकवादी गतिविधि को एक ऐसी गतिविधि के रूप में परिभाषित करता है जो भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने या लोगों के मन में आतंक पैदा करने का इरादा रखती है। इसे या तो विस्फोटक या घातक हथियारों या खतरनाक प्रकृति के किसी अन्य पदार्थ के माध्यम से बनाया जा सकता है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट लग सकती है और किसी संपत्ति का विनाश हो सकता है। यह राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक लक्ष्यों के लिए आबादी या सरकार को डराने के लिए नागरिकों के खिलाफ हिंसा का एक

व्यवस्थित उपयोग है। सीमा पार आतंकवाद में अपरंपरागत रणनीति जैसे साइबर हमलें, राजनीतिक युद्ध, धारणा युद्ध, सशस्त्र प्रॉक्सी सेनानियों का प्रायोजन आदि शामिल हैं। आतंकवाद की एक सामान्य परिभाषा राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक लक्ष्यों के लिए आबादी या सरकार को डराने के लिए व्यवस्थित उपयोग या हिंसा का धमकी भरा उपयोग है।

भारत एक भौगोलिक-विविध देश है और भारतीय उपमहाद्वीप का एक हिस्सा है। भारत सात अंतरराष्ट्रीय देशों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। विभिन्न प्रकार के प्रशासन, कट्टरपंथी और भाषाई विविधता एक साथ मौजूद हैं और विविध धर्म विभिन्न प्रकार की विचारधारा, रीति-रिवाजों और व्यापार का निर्माण करते हैं, जिसका अध्ययन पहली बार कार्ल ओस्ट्रोवर जैसे सांस्कृतिक भूगोलवेत्ताओं ने किया था। अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं और सीमाओं की पहचान के कारण राजनीतिक भूगोलवेत्ताओं द्वारा सीमा पार आतंकवाद की पहचान एक नया दृष्टिकोण है।

जब एक देश की धरती का उपयोग राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक लक्ष्यों के लिए सीमा पार अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ आतंक पैदा करने या आतंकवाद में शामिल होने के लिए किया जाता है, तो इसे सीमा पार आतंकवाद कहा जाता है। सीमा पार आतंकवाद में हिंसा के उद्देश्य से और भौगोलिक क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने के उद्देश्य से जातीय समूह का एक व्यक्ति अवैध रूप से सरकार की अनुमति के बिना प्रवेश करता है। भूगोलवेत्ताओं ने सीमा पार आतंकवाद के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारणों की पहचान की जैसे कि स्थान की रणनीतिक स्थिति, क्षेत्रीय आकांक्षा, कट्टरवाद, या किसी स्थान की जलवायु या आर्थिक भूविज्ञान। उदाहरण के लिए उत्तर पूर्व भारत में सीमा पार आतंकवाद विशेष रूप से नागालैंड के लोगों द्वारा अलगाव की मांग से निर्देशित है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से सीमा पार आतंकवाद की कट्टरपंथी सोच है जबकि नेपाल से घुसपैठ माओवादी विचारधारा द्वारा निर्देशित है।

भारतीय सीमा

भारत की 15,106.7 कि.मी. लंबी भू-सीमा और 7,516.6 कि.मी. की तटरेखा है, जिसमें द्वीप क्षेत्र शामिल हैं। छह राज्यों (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, दिल्ली और हरियाणा) को छोड़कर भारत

के कुल 29 राज्यों में से बाकी सभी राज्यों की समुद्री सीमा या अन्य देशों के साथ भूमि सीमा है। भारत की भूमि सीमाएँ निम्न देशों के साथ हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान (पीओके), चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत की सात देशों के साथ समुद्री सीमाएँ हैं: बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका और मालदीव।

भारत-पाकिस्तान सीमा

भारत-पाकिस्तान सीमा (3,323 कि.मी.) गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथ-साथ चलती है। सीमाओं की सीधी पहुँच और सूचना के त्वरित मार्ग और धन के हस्तांतरण को सक्षम करने वाले कुछ तकनीकी विकास ने सीमा सुरक्षा के फोकस और सिद्धांत को बदल दिया है। पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद अपने आतंकवादी समूहों द्वारा सीमाओं की मान्यता न देने और धार्मिक या जातीय पहचान के कारण वैधता प्राप्त करने में उनकी सफलता के कारण बढ़ गया है। पाकिस्तान के अपर्याप्त सहयोग ने भारत के लिए सीमा प्रबंधन को और कठिन बना दिया है।

भारत-बांग्लादेश सीमा

भारत-बांग्लादेश सीमा (4,096 किलोमीटर) पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। पूरे खंड में मैदान, नदी के किनारे के क्षेत्र, पहाड़ियाँ और जंगल हैं जो अवैध प्रवासन को बहुत आसान बनाते हैं। इस सीमा के पार अवैध प्रवास गंभीर सुरक्षा खतरे पैदा करता है और पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस जैसे संगठनों के लिए अपनी गतिविधियों में घुसने और विस्तार करने के लिए एक उपजाऊ जमीन के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, सीमा पर खराब कानून व्यवस्था की वजह से हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी हुई है। हथियारों की आपूर्ति किसी भी संघर्ष को बनाए रखने में मदद करती है।

भारत-चीन सीमा

भारत जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चीन के साथ एक लंबी भूमि सीमा (3,488 किलोमीटर) साझा करता है। हालाँकि यह सीमा अवैध प्रवासन से अपेक्षाकृत अलग रहती है, फिर भी यह सीमा भारतीय सेनाओं के लिए निरंतर चौकसी का कारण बनी हुई है। अक्सर चिन

और अरुणाचल प्रदेश में ब्रिटिश काल से चला आ रहा चीन के साथ भारत का पुराना सीमा विवाद है।

भारत-नेपाल सीमा

भारत-नेपाल सीमा (1,751 किमी) इस अर्थ में एक खुली सीमा है कि कई स्थानों पर सीमा चौकियों के अस्तित्व के बावजूद दोनों देशों के लोग इसे किसी भी बिंदु से पार कर सकते हैं। भारत विरोधी संगठन इस सीमा का उपयोग भारत के क्षेत्र में अपने लोगों को लगाने के लिए करते हैं। साथ ही, सोने, छोटे हथियारों, ड्रग्स और नकली नोटों की तस्करी से भी आतंकियों को हमले को अंजाम देने में मदद मिलती है।

भारत-भूटान सीमा

यह सीमा (699 किमी) असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों से होकर गुजरती है। दक्षिण-पूर्व भूटान के घने जंगलों में आतंकवादी संगठनों द्वारा शिविरों की अवैध स्थापना से भारत के विद्रोहियों को भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद मिलती है।

भारत-म्यांमार सीमा

अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के पूर्वोत्तर राज्य म्यांमार (1,643) के साथ सीमा साझा करते हैं। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN) और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम (ULFA) जैसे कुछ विद्रोही समूह म्यांमार से काम करते हैं, जो भारत के साथ-साथ म्यांमार की सुरक्षा के लिए भी खतरा है।

समुद्री सीमाओं के माध्यम से सीमा पार आतंकवाद

न केवल भूमि सीमाओं वाले सीमावर्ती राज्य सीमा पार आतंकवाद के प्रति संवेदनशील हैं, बल्कि तटीय क्षेत्र भी समान रूप से असुरक्षित हैं। देश की लंबी तटरेखा अपेक्षाकृत असंरक्षित रहती है। भारत को सीमा प्रबंधन के संबंध में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तटरक्षक बल की उपस्थिति न्यूनतम है। 26/11 में हमले में आतंकवादी नावों के जरिए पश्चिमी तट से आए थे। समय के साथ घुसपैठियों ने तटीय क्षेत्र पार करने के कई तरीके ईजाद किए हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ आंतरिक रूप से सीमा प्रबंधन से जुड़ी हुई हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय विद्रोही समूहों को लंबे समय से शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों द्वारा देश की सीमाओं पर आश्रय प्रदान किया गया है।

सीमा पार आतंकवाद के अन्य कारण

1. विशेष रूप से संचार लिंक के संदर्भ में तकनीकी प्रगति जिसके कारण कट्टरपंथी समूहों को अधिक परिष्कृत हथियार, सेल फोन और उच्च गति के इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता हुई है।
2. वर्तमान आतंकवादी समूह अपने स्लीपर सेल और विभिन्न स्थानीय समूहों में वृद्धि के साथ अपनी संरचना में अधिक फैले हुए हैं।
3. विभिन्न आतंकवादी संगठनों को राज्य-प्रायोजित और अच्छे आतंकवादी और बुरे आतंकवादी के रूप में भेदभाव करने वाले आतंकवादी संगठन हैं जैसे अच्छा और बुरा तालिबान ।
4. कट्टरवाद की अत्यधिक भावना और मौलिक समूहों के प्रति वैचारिक झुकाव।
5. खराब शासन और अभाव।

कुछ राजनीतिक भूगोलवेत्ताओं के अनुसार, भारत की विकासशील प्रकृति और रोस्तोव द्वारा प्रदान किए गए मॉडल के अनुसार, भारत विकासशील से विकसित अवस्था में परिवर्तित हो रहा है और उच्च निवेश और विनिर्माण गतिविधियों द्वारा निर्देशित है। भारत एशिया में क्षेत्रीय शक्ति के लिए अनुकूलन कर रहा है जो कुछ अन्य उभरते देशों के साथ संघर्ष में है, जो भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए सीमा पार आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय राजनीतिक विचारकों ने दो प्रकार के सीमा पार आतंकवाद को मान्यता दी, जो कि सूक्ष्म स्तर पर सीमा पार आतंकवाद और वृहद स्तर पर सीमा पार आतंकवाद है। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार आतंकवाद में परिणत होती हैं, जबकि देश की सांस्कृतिक और जातीय विविधता और प्रशासन की अर्ध-संघीय प्रकृति सूक्ष्म या राष्ट्रीय सीमा पार आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए पुणे बेकरी पर अल-कायदा का हमला अंतरराष्ट्रीय सीमा पार आतंकवाद का एक उदाहरण है, जबकि छत्तीसगढ़ और असम में हिंसा सूक्ष्म स्तर के सीमा पार आतंकवाद का उदाहरण है।

सीमा पार आतंकवाद के परिणाम

सीमा पार आतंकवाद से जुड़े कई परिणामों की पहचान की गयी है जो इस प्रकार हैं:

1. राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा

2. क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन में बाधा
3. सांस्कृतिक क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण और क्षेत्रवाद की धारणा।
4. संपत्ति, मानव संसाधन, वनस्पतियों, समग्र विविधता और जीवों की हानि।

सीमा पार आतंकवाद को नियंत्रित करने की रणनीतियाँ

राजनीतिक विचारको ने सीमा पार आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए कुछ राजनीतिक और भौगोलिक रणनीतियों का सुझाव दिया है जो इस प्रकार हैं:-

1. सीमाओं और सीमाओं पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन करना।
2. क्षेत्र विशिष्ट लोगों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिये यू. एन.सी.एल.ओ.एस. का प्रभावी कार्यान्वयन।
3. भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और संबंधित उपग्रह जैसे- आर.आई.एस.ए. टी.-1 और जी.सैट-1 के रूप में नवीनतम प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग।
4. सार्क राष्ट्र हिंद महासागर आर.आई.एम. देशों और एन.सी.टी.सी., आई.बी., रॉ जैसी राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच क्षेत्रीय सहयोग।
5. भारत एफ.ए.टी.एफ (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी सदस्य है, जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करना है।
6. व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) ने पता लगाने और अवरोधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की मैनुअल निगरानी/गश्त को बदल दिया है।

सीमा पार आतंकवाद से निपटने के उपाय

1. सीमा के साथ-साथ बुनियादी ढाँचे में सुधार करना होगा – त्वरित गतिशीलता के लिए सड़क संपर्क के साथ-साथ रेल संपर्क प्रदान करना होगा।
2. सीमाओं से जुड़े प्रमुख और छोटे व्यापार मार्गों के साथ-साथ अतिरिक्त चौकियों और सीमा चौकियों का निर्माण।

3. फ्लोटिंग पुलों, दीवारों और बिजली की बाड़ का निर्माण जहाँ घुसपैठ की उच्च संभावना हो।
4. म्यांमार, भूटान और नेपाल जैसे देशों के साथ संयुक्त सीमा प्रबंधन करना।
5. सीमाओं के आसपास के गांवों में स्वास्थ्य सेवा, भौतिक बुनियादी ढांचे और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करके उन्हें सीमा प्रबंधन में हितधारक बनाना।
6. सीमा प्रबंधन पर माधव गोडबोले टास्क फोर्स की सिफारिशों को लागू करने की जरूरत है।
7. सी.आर.पी.एफ. को प्राथमिक राष्ट्रीय स्तर के उग्रवाद विरोधी बल के रूप में नामित किया जाना चाहिए। यह अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों जैसे बी.एस.एफ. और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस को बेहतर सीमा प्रबंधन की अपनी प्राथमिक भूमिका में लौटने में सक्षम करेगा।
8. अस्थिर सीमाओं का प्रबंधन करने वाले सभी अर्धसैनिक बलों को सीधे सेना के नियंत्रण में काम करना चाहिए और यह कि सेना से अर्धसैनिक बलों को पार्श्व प्रवेश दिया जाना चाहिए ताकि उनकी परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके।
9. यदि सीमाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना है तो 'एकल बिंदु नियंत्रण' के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए।
10. निगरानी प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से उपग्रह और हवाई इमेजनरी में प्रगति, एल.ए.सी. पर निरंतर निगरानी बनाए रखने में मदद कर सकती है और भौतिक तैनाती को कम करना संभव बनाती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

1. भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के प्रबंधन जैसे खुफिया तंत्र, आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन से संबंधित कई मुद्दों पर हमारी नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।
2. आप्रवासन पर कड़ा नियंत्रण लागू करें।
3. आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए अधिक प्रभावी घरेलू समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
4. सेना को एल.ओ.सी. और एल.ए.सी. के पार आतंकी शिविरों पर हमले के वैकल्पिक तरीकों पर भी ध्यान देना चाहिए जैसे सटीक जुड़ाव क्षमता जैसे तंत्र के माध्यम से।

5. सीमा सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों को बढ़ाने और पूरक करने के लिए तकनीकी समाधान आवश्यक है।
6. केंद्र और राज्य स्तर पर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के बीच घनिष्ठ और प्रभावी समन्वय बनाए रखना।।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

1. भारत सरकार ने मुंबई हमलों के बाद 2008 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) बनाई है जो आतंक का मुकाबला करने के लिए एक संघीय एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
2. मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) 26/11 के हमलों के बाद पुनर्निर्मित, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक बहु-एजेंसी खुफिया समन्वय तंत्र के रूप में कार्य करता है।
3. आतंकवाद के वित्तपोषण और नकली भारतीय मुद्रा का मुकाबला करने पर नीतिगत मामलों से निपटने के लिए आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने वाला सेल (CFT- सेल) भी बनाया गया है।
4. भारत एफ.ए.टी.एफ. (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) का भी सदस्य है, जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित करना है।
5. एफ.ए.टी.एफ. ने पाकिस्तान को अपनी 'ग्रे-लिस्ट' या 'बढ़ी हुई निगरानी सूची' से हटा दिया है। एफ.ए.टी.एफ. में संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.) शामिल था, जिसके साथ भारत ने फरवरी 2021 में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए।
6. सरकार ने बढ़ते अप्रवासन को रोकने के लिए निरीक्षण चौकियाँ, सीमा पर बाड़ लगाना, फ्लड लाइटिंग, आधुनिक और हाई-टेक निगरानी उपकरणों की तैनाती की है।
7. व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) पता लगाने और अवरोधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की मैन्युअल निगरानी/गश्त को बदल दिया है।
8. भारत आतंकवाद से निपटने के लिए विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र में सभी प्रयासों का समर्थन करता रहा है और अंतरराष्ट्रीय राय को आकार देने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को प्राथमिकता देने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करने में अग्रणी भूमिका निभाई है।
9. 1996 से भारत एक वैश्विक अंतर-सरकारी सम्मेलन यानी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (CCIT) को आगे बढ़ाने

की कोशिश कर रहा है। 1996 से भारत आतंकवाद से निपटने के लिए यह आतंकवादियों के अभियोजन और प्रत्यर्पण को बढ़ाने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान कर सकता है।

10. समय-समय पर पड़ोसी देशों के साथ उनके संबंधित क्षेत्रों में पनप रहे आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए लगातार संवाद शुरू किए गए हैं।

11. भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के प्रबंधन जैसे खुफिया तंत्र, आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन से संबंधित कई मुद्दों पर पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

12. सीमा सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों को बढ़ाने और पूरक करने के लिए तकनीकी समाधान आवश्यक हैं।

13. वे न केवल सीमा सुरक्षा बलों की निगरानी और पहचान क्षमताओं को बढ़ाते हैं बल्कि घुसपैठ और सीमा पार अपराधों के खिलाफ सीमा सुरक्षा कर्मियों के प्रभाव में भी सुधार करते हैं।

14. भारत को सीमा पार आतंकवाद से लड़ने के लिए सेना की विशेषज्ञता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

15. सेना को एल.ओ.सी. (नियंत्रण रेखा) और एल.ए.सी. (वास्तविक नियंत्रण रेखा) के पार आतंकी शिविरों पर हमला करने के वैकल्पिक तरीकों को भी देखना चाहिए। सटीक सगाई क्षमता जैसे तंत्रों के माध्यम से हमला करने के वैकल्पिक तरीकों को भी देखना चाहिए।

16. उचित रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति और सस्ती और परीक्षण की गई तकनीक के विवेकपूर्ण मिश्रण से बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है।

17. आतंकवाद के खिलाफ युद्ध एक कम तीव्रता वाला संघर्ष या स्थानीय युद्ध है और इसे समाज के पूर्ण और निरंतर समर्थन के बिना नहीं छेड़ा जा सकता है और अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए समाज का मनोबल और संकल्प लड़खड़ाता है तो आसानी से हार सकता है।

निष्कर्ष

किसी भी देश के लिए किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों या उनके माध्यम से घुसपैठ को रोकने के लिए अपनी सीमा पर कड़ी निगरानी रखना बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के लिए यह कार्य कठिन हो जाता है। जहाँ इसके कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में इलाके और जलवायु बहुत जटिल

हैं। बेहतर तकनीक पर ध्यान केंद्रित करने से सुरक्षा बलों के काम को आसान बनाने और अपनी सीमाओं को और अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। सीमाएँ, हाल के वर्षों में क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक विविधता को उचित देखभाल प्रदान करके शांति और समृद्धि का प्रतीक हैं। सीमा पार आतंकवाद इस पहचान और सांस्कृतिक विविधता के लिए खतरा है। इसलिए यह भूगोलवेत्ताओं और राजनीतिक विचारकों की जिम्मेदारी है कि वे किसी क्षेत्र के भूगोल, जनसांख्यिकीय विशेषताओं और क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता की जांच करें और उन नीतियों की वकालत करें जो भारत के लोगों के उच्च हित में हैं।

सन्दर्भ :

शर्मा विश्वेश, 'आतंकवाद व जनसाझेदारी', पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय नई दिल्ली.

पाण्डेय, डॉ० राम सूरत, 'स्त्रातजिक विचारधारा उद्भव व विकास', प्रकाश बुक डिपो, बरेली

फाड़िया, बी. एल., 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध', साहित्य भवन पब्लिकेशन्स

सिंह, डॉ० अशोक कुमार, 'राष्ट्रीय सुरक्षा', प्रकाश बुक डिपो, बरेली

कुमार, अशोक IPS, 'भारत की आंतरिक सुरक्षा मुख्य चुनौतियाँ', Mc Graw Hill Education, Chennai.

पाण्डेय, डॉ० राम सूरत, 'राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध', प्रकाश बुक डिपो, बरेली

<https://www.mha.gov.in/en/documents/annual-reports>

https://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/34894_MEA_Annual_Report

<https://mod.gov.in/annual-report>

<https://hi.wikipedia.org/wiki/आतंकवाद>

<https://www.insightsonindia.com/security-issues/terrorism/cross-border-terrorism/>

<https://edurev.in/t/213477/Cross-border-Terrorism>

<https://www.drishtiias.com/to-the-points/paper3/cross-border-terrorism>

<https://old.mu.ac.in/wp-content/uploads/2014/04/Hindi-National-seminar-india-pakistan-terrorism2.pdf>

Copyright © 2025 Siri Research Foundation. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY-NC-ND 4.0).